



Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 21-2018] CHANDIGARH, TUESDAY, MAY 22, 2018 (JYAISTHA 1, 1940 SAKA)

General Review

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग हरियाणा की वर्ष 2016-17 की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट की समीक्षा।

दिनांक 6 फरवरी, 2018

No. Admn./431/2015/ISIT/6622.—

1. विभाग और इसकी स्वायत्त निकायों का बजट और व्यय :

विभाग ने 8873.90 लाख रुपये के स्वीकृत बजट में से वर्ष 2016-17 के दौरान इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, आईटीइज गतिविधियों में केवल 7265.59 लाख रुपये खर्च किए। भारत सरकार से फण्ड प्राप्त न होने और रिक्त पदों के कारण खर्च में कमी आई। विभाग में कोई राजस्व स्कीम नहीं है। यद्यपि, 600550 रुपये की राशि लाभांश और आरटीआई फीस के रूप में प्राप्त हुई।

- (क) **हरियाणा राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड :-** निगम का बजट और खर्च — 4870.50 लाख रुपये के बजट कारोबार के मुकाबले वर्ष 2016-17 में निगम का कारोबार 5155.85 लाख रुपये हुआ। इसी प्रकार 4285.50 लाख रुपये के बजट व्यय के मुकाबले वर्ष 2016-17 के लिए व्यय 4699.73 लाख रुपये रहा। अनुमानित लाभ 375.70 लाख रुपये के मुकाबले वर्ष 2016-17 के लिए शुद्ध लाभ 249.86 लाख रुपये रहा।
- (ख) **हरियाणा नॉलेज निगम लिमिटेड :-** कम्पनी का बजट और व्यय — बजट कारोबार 915.00 लाख रुपये के मुकाबले वर्ष 2016-17 के लिए कम्पनी का कारोबार 834.65 लाख रुपये था। बजट खर्च 640.00 लाख रुपये के मुकाबले वर्ष 2016-17 के लिए व्यय 599.62 लाख रुपये था। अनुमानित लाभ 275.00 लाख रुपये के मुकाबले वर्ष 2016-17 के लिए शुद्ध लाभ 235.03 लाख रुपये रहा।
- (ग) **ई-शासन आईटी पहल कोष :-** सोसाइटी के वित्तीय परिणाम — वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान सोसाइटी ने कुल 4.33 करोड़ रुपये की आय अर्जित की। यह आय मुख्यतः विभिन्न बैंकों में एफडीआर के ब्याज और बचत बैंक खाता के ब्याज के कारण है। इन कुल प्राप्तियों के विरुद्ध सोसाइटी ने 2.09 करोड़ रुपये का व्यय किया, जिससे वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान 2.24 करोड़ रुपये सरप्लस अर्जित किए।

2. हरियाणा से इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, आईटीइज उद्योग एवं सॉफ्टवेयर निर्यात :-

- (क) घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय निवेशकों के पसंदीदा निवेश स्थल के रूप में उभरता हरियाणा आज अनेक बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और कार्पोरेट हाउसिज का घर है। वर्ष 2015-16 के दौरान विभाग द्वारा आईटीइज/बीपीओ/इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग फैक्टरी को अनेक प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए आईटी एवं ईएसडीएम पुलिसि, उद्यम एवं स्टार्ट-अप पुलिसि, संचार एवं संयोजकता अवसंरचना पुलिसि और साइबर सेक्यूरिटी पुलिसि शुरू की गई। इनका उद्देश्य निवेशक मैत्री वातावरण सृजित कर निवेश सुविधाएं प्रदान करना, शीघ्र स्वीकृतियां प्रदान करना और विश्वसनीय अवसंरचना विकसित करना है। इन नीतियों का अधिकांश कार्य वर्ष 2016-17 के दौरान पूरा किया गया।
- (ख) उपरोक्त के अतिरिक्त, इस वर्ष के दौरान विभाग द्वारा ई-मेल नीति और सरकारी आईटी संसाधनों के उपयोग की पुलिसि जारी की गई है। हरियाणा ई-सेवा स्कीम के तहत उत्साहवर्धक प्रतिक्रिया मिलने के कारण वर्ष के दौरान इसमें विभिन्न विभागों, संगठनों की 75 अन्य सेवाओं को भी शामिल किया गया, जिनको मिलाकर कुल 298 सेवाएं हो गई हैं।
- (ग) आईटी/आईटीइज सेक्टर में स्वीकृत कुल 28 एसईजैड में से 6 एसईजैड चालू हो गये हैं और शेष विकास की प्रक्रियाधीन हैं।
- (घ) इस वर्ष तक 12000 करोड़ रुपये से अधिक के परियोजना निवेश के साथ लगभग 603.99 एकड़ भूमि पर आईटी/आईटीइज पार्कों की स्थापना के लिए प्राइवेट उद्यमियों को 49 लाइसेंस दिए जा चुके हैं तथा एचएसआईआईडीसी ने हरियाणा के चार स्थलों यानि पंचकूला, आईएमटी मानेसर, कुण्डली और राई (सोनीपत) में कुल 5696 करोड़ रुपये के निवेश से आईटी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए टैकनोलोजी पार्क/इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर टैकनोलोजी पार्क का इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित करने में पर्याप्त प्रगति की है।
- (ङ) इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन और निर्माण (ईडीएसएम) सेक्टर के विकास में सहायता करने के लिए जिला गुरुग्राम के क्षेत्र, तहसील बावल, सब-तहसील धारुहेड़ा, बरवाला खण्ड और अन्य औद्योगिक क्षेत्र सहित जिला पंचकूला, जिला फरीदाबाद, जिला पलवल, जिला अम्बाला, जिला यमुनानगर, जिला झज्जर और जिला सोनीपत में राज्य सरकार या इसके स्थानीय प्राधिकरण द्वारा कुण्डली व राई क्षेत्र सहित सभी स्वीकृत औद्योगिक क्षेत्रों को भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है।
- (च) प्रदेश में आईटी और आईटी सक्षम सेवा उद्योगों के वर्तमान विकास परिदृश्य को देखते हुए विभाग ने गुरुग्राम के बाद पंचकूला में नया एसटीपीआई सेंटर की स्थापना करने के लिए कदम उठाए हैं, जिसके लिए एचएसआईआईडीसी से भूमि की खरीद की जा चुकी है।
- (छ) वर्ष 2016-17 के दौरान, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी क्षेत्र में भारत से कुल निर्यात 116.01 बिलियन यूएसडी डॉलर होने का अनुमान है, जिसमें हरियाणा का हिस्सा 6.2 प्रतिशत है, जो लगभग 7.2 बिलियन यूएसडी डॉलर बनता है। इस समय देश भर के आईटी. सेक्टर में रोजगार का 6.8 प्रतिशत राज्य के खाते में है। दो लाख से अधिक व्यक्ति आईटी./आईटीइज सेक्टर में कार्यरत हैं।

3. आईसीटी इन्फ्रास्ट्रक्चर

- (क) **स्वान**—स्वान स्कीम के तहत सभी जिला मुख्यालयों, खण्डों, उपमण्डलों, तहसीलों, उप-तहसीलों, हरियाणा सिविल सचिवालय और हरियाणा भवन, नई दिल्ली को लम्बवत (वर्टिकली) जोड़ा गया है और विभिन्न विभागों के 1277 कार्यालयों को होरिजेंटली जोड़ा गया है। इसके अतिरिक्त, स्टेट डाटा सेंटर भी स्थापित किया गया है और डाटा सेंटर पर विभिन्न विभागों/संगठनों और ई-जिला परियोजनाओं की 75 एप्लिकेशन होस्ट की गई है।
- (ख) **एनओएफएन** :- नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नैटवर्क के तहत इस वर्ष के दौरान 4051 ग्राम पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने का कार्य पूरा किया गया और जिला फरीदाबाद, सोनीपत, रेवाड़ी और महेन्द्रगढ़ के गांवों में वाईफाई होटस्पॉट सिस्टम लगाए गए।
- (ग) **एसकेज** :- 4000 अटल सेवा केन्द्रों की स्थापना की गई और इसके तहत 170 विभागों की सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक पद्धति में शुरू किया गया और 125 ई-दिशा केन्द्रों में 37,94,725 लेन-देन किए गये।
- (घ) **आधार नामांकन** :- आधार नामांकन के तहत राज्य ने 2015 की आबादी के आधार पर 103 प्रतिशत आधार परिपूर्णता हासिल की है।

4. ई-सेवाएं :-

- (क) नागरिकों के लाभ के लिए 296 ई-सेवाएं ऑनलाइन प्रदान की गईं यानि अटल सेवा केन्द्रों और ई-दिशा केन्द्रों के माध्यम से 170 सरकार से नागरिकों को (जी2सी) ई-सेवाएं, स्टेट पोर्टल पर 15 जी2सी सेवाएं, भारत सरकार की 12 जी2सी सेवाएं और 99 बिजनेस से नागरिकों की (बी2सी) सेवाएं प्रदान की गईं।

- (ख) **आरएस (तत्काल मूल्यांकन प्रणाली) का एकीकरण :-** 67 विभागीय एप्लीकेशनस (राजस्व, कृषि, गृह, एचएसआईआईडीसी, सामाजिक न्याय, खेल, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी और मत्स्य पालन) को आरएस पर एकीकृत किया गया। इसके अतिरिक्त, 50 जी2सी सेवाओं को यूएमएनजी के माध्यम से नागरिकों को उपलब्ध करवाने की योजना बनाई गई।

5. ई-गवर्नेंस एप्लीकेशन :-

दक्षता में सुधार लाने, विलम्बता में कमी लाने, पारदर्शिता और व्यापार करने की सहूलियत बढ़ाने के दृष्टिगत विभिन्न विभागों ने ई-गवर्नेंस एप्लीकेशन शुरू की हैं।

- (i) **सीएम विंडो :-** सीएम विंडो पर कुल 2,55,595 शिकायतें प्राप्त की गई, जिसमें से 2,28,617 शिकायतों का निपटारा किया गया।
- (ii) **राजस्व विभाग :-** भूमि पंजीकरण प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने हेतु सम्पत्ति पंजीकरण के लिए ई-पंजीकरण अच्वाइंटमेंट के लिए एप्लीकेशन का क्रियान्वयन तथा साथ ही व्यापार की सहूलियत प्रदान करने के लिए ई-स्टॉम्पिंग की शुरुआत की गई।
- (iii) **सीएम ई-डैशबोर्ड :-** विभागों के महत्वपूर्ण प्रदर्शन संकेतकों की निगरानी करके विभागों की दक्षता में सुधार लाने के लिये ई-डैशबोर्ड स्थापित किया गया।
- (iv) **ई-पीएमएस (परियोजना प्रबन्धन प्रणाली) -** केन्द्र और राज्य सरकार की 10 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की महत्वपूर्ण परियोजनाओं की निगरानी करने के लिए परियोजना प्रबन्धन प्रणाली का क्रियान्वयन किया गया।
- (v) **खाद्य एवं आपूर्ति :-** खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने टीपीडीएस का आद्योपांत कम्प्यूटरीकरण की शुरुआत की, जिसमें डाटा डिजिटलीकरण, राशनकार्ड प्रबन्धन प्रणाली, ऑनलाइन आबंटन एवं आपूर्ति श्रृंखला प्रबन्धन और एफपीएस स्वचालन शामिल है। एनएफएसए-2013 ढांचे के तहत लाभार्थियों का डाटाबेस चिन्हित किया गया, जो राष्ट्रीय डाटा मानकों का अनुपालन करता है।
- (vi) **ई-बिज पोर्टल :-** ई-बिज पोर्टल एक ऐसा ऑनलाइन पोर्टल है, जो एकल प्लेटफार्म पर समयबद्ध तरीके से निवेशकों को औद्योगिक स्वीकृतियां प्रदान करने और उनकी शिकायतों का समाधान करने में सक्षम बनाता है। इस पर 35 से अधिक सेवाएं उपलब्ध करवाई गई।
- (vii) **एचएसआईआईडीसी ई-सेवा पोर्टल :-** नागरिक सेवाएं जैसे प्लॉट्स/स्थलों का आबंटन, सम्पदा प्रबन्धन की आबंटन उपरांत की स्वाचलन प्रक्रिया और पानी व सीवरज बिलिंग की प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन पोर्टल सृजित किया गया।
- (viii) **जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण :-** जन्म पंजीकरण के साथ आधार नामांकन का एकीकरण करने के लिए ऑनलाइन जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण का क्रियान्वयन किया गया।
- (ix) **अध्यापक स्थानान्तरण नीति :-** स्कूल शिक्षा विभाग ने अध्यापक स्थानान्तरण नीति 2016 अधिसूचित की और इसे प्रबन्धन सूचना प्रणाली के साथ एकीकृत किया गया है।
- (x) **रेजिडेंट डाटाबेस (एसआरडीबी) :-** आधार कोष में लगभग 1.68 करोड़ नागरिकों का रिकॉर्ड समाहित है। विभिन्न विभागों की 29 ई-सेवाओं को एक्सचेंज डाटा से एसआरडीबी के साथ एकीकृत किया गया।
- (xi) **ई-ऑफिस प्रोजेक्ट :-** (1) आईटी विभाग (2) एनआईसी (3) हार्दोन (4) आईआईटी (5) जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग में प्राथमिकता के आधार पर ई-ऑफिस शुरू करने की योजना बनाई गई।

6. वित्तीय लेनदेन इलेक्ट्रॉनिक व कैशलेस करना :-

- (क) राज्य ने सभी अदायगियां इलेक्ट्रॉनिक मॉड के द्वारा की हैं। वर्ष के दौरान राज्य के खजानों द्वारा 54,415.91 करोड़ रुपये की राशि की 91.12 प्रतिशत अदायगी इलेक्ट्रॉनिक रूप से की गई और 1890.30 करोड़ रुपये की लगभग 4.45 प्रतिशत अदायगी एजी और बैंक द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से पेंशनभोगियों को की गई।
- (ख) राज्य ने इंटरनेट बैंकिंग और पे-मेंट एग्रीगेटर्स का उपयोग करके क्रेडिट-डेबिट कार्ड के माध्यम से स्टेट टैक्स की ऑनलाइन अदायगी करने की सुविधा प्रदान की है। वर्ष के दौरान 55 प्रतिशत लेनदेन ऑनलाइन किया गया। इसके अतिरिक्त, एनईएफटी/आरटीजीएस और पीओएस मशीनों के माध्यम से अदायगी की गई।
- (ग) **प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण -** वर्ष के दौरान राज्य वृद्धावस्था पेंशन, खाद्य सब्सिडीज व छात्रवृत्ति में डीडुप्लीकेशन के कारण 250 करोड़ रुपये बचा सका।

- (घ) वित्त विभाग ने कर्मचारियों के उनके समस्त सेवाकाल के मामलों का पता लगाने के लिए एचआरएमएस (मानव संसाधन प्रबन्धन प्रणाली) और आय व व्यय के बेहतर वित्त प्रबन्धन के लिए आईएफएमएस (समेकित वित्त प्रबन्धन प्रणाली) लागू की ।
- (ङ) **वाणिज्यिक कर** — विभाग ने मूल्य संवर्धन कर प्रबन्धन, आंकलन, संग्रहण प्रणाली शुरू की है, जो सी फार्म, ई-अनुप्रयोग, ई-रिटर्न इत्यादि जैसी ऑनलाइन ई-सेवाएं प्रदान करती हैं और आबकारी विभाग को जीएसटी तैयार करने में सक्षम बनाती है।

7. कौशल विकास कार्यक्रम :-

- (क) **राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन** — इस कार्यक्रम के तहत अटल सेवा केन्द्रों द्वारा 2,26,928 उम्मीदवारों को ऐप्रीसिएशन ऑफ डिजिटल साक्षरता (लेवल-1) कोर्स में प्रशिक्षित किया गया और 1,31,047 उम्मीदवारों ने सफलतापूर्वक यह परीक्षा उत्तीर्ण करके भारत सरकार से अपने डिजिटल साक्षरता सर्टिफिकेट प्राप्त किए।
- (ख) हारट्रोन द्वारा प्रदेशभर में 80 ई-शिक्षा केन्द्रों के माध्यम से युवाओं को आईटी कौशल में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 30000 युवाओं को प्रशिक्षित किया गया । हारट्रोन ने बहुकौशल विकास कार्यक्रम के तहत 1204 वीएलईज को प्रशिक्षित किया ।
- (ग) **हरियाणा नॉलेज कार्पोरेशन लिमिटेड (एचकेसीएल)** : हरियाणा नॉलेज कार्पोरेशन लिमिटेड (एचकेसीएल) ने 245 फ्रेंचाइज सेंटरों की स्थापना की है जिसके तहत वर्ष के अन्त तक 20,924 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया ।
- (घ) उपरोक्त के अतिरिक्त, सरकार ने अब तक 36 हजार से अधिक सरकारी कर्मचारियों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्रदान किया है।

8. विभागाध्यक्ष :-

रिपोर्ट अधीन वर्ष के दौरान निम्न प्रशासनिक सचिव और सचिव के पद पर आसीन रहे —

(क) प्रशासनिक सचिव

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| (i) श्रीमती केसनी आनन्द अरोड़ा, आईएएस | 01.04.2016 से 01.05.2016 |
| (ii) श्री देवेन्द्र सिंह, आईएएस | 02.05.2016 से 31.03.2017 |

(ख) सचिव/विशेष सचिव

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| (i) श्री विजयेन्द्र कुमार, आईएएस | 01.04.2016 से 25.04.2016 |
| (ii) श्री ए श्रीनिवास, आईएएस | 26.04.2016 से 13.12.2017 (अपराह्न) |
| (iii) श्री विजयेन्द्र कुमार, आईएएस, | 13.02.2017 (दोपहर बाद) से 31.03.2017 |

चण्डीगढ़:
दिनांक 6 फरवरी, 2018.

देवेन्द्र सिंह,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग।

**REVIEW OF ANNUAL ADMINISTRATIVE REPORT OF ELECTRONICS & INFORMATION
TECHNOLOGY DEPARTMENT, HARYANA FOR THE YEAR 2016-17**

The 6th February, 2018

No. Admn./431/2015/ISIT/6622.—

1. Budget and Expenditure of the Department and its autonomous bodies:

Out of the approved budget of Rs. 8873.90 lac, Department has incurred Rs 7265.59 lac only during the year 2016-17 in Electronics/IT/ITES activities. Short fall in expenditure due to non-receipt of funds from Government of India and vacant posts. There is no revenue scheme in the department. However an amount of Rs.6,00,550/- was received as Dividend and RTI fee.

- (a) **Haryana State Electronics Development Corporation Ltd:-** Budget and Expenditure of the Corporation: - The turnover of the Corporation for the year 2016-17 was Rs. 5155.85 lakh as against the budgeted turnover of Rs. 4870.50 lakh. The expenditure for the year 2016-17 was Rs. 4699.73 lakh as against the budgeted expenditure of Rs. 4285.50 lakh. The net profit for the year 2016-17 was Rs. 249.86 lakh as against the estimated profit of Rs. 375.70 lakh.
- (b) **Haryana Knowledge Corporation Ltd:-** Budget and Expenditure of the Company: The turnover of the Company for the year 2016-17 was Rs. 834.65 lakh (including interest income) as against the budgeted turnover of Rs.915.00 lakh. The expenditure for the year 2016-17 was Rs. 599.62 lakh as against the budgeted expenditure of Rs. 640.00 lakh. The net profit for the year 2016-17 before tax was Rs.235.03 lakh as against the estimated profit of Rs. 275.00 lakh.
- (c) **Society for IT Initiative Fund for e-Governance:-**Financial results of the Society: During the financial year 2016-17, the Society earned total income of Rs 4.33 crores. This income was mainly on account of interest from FDR held with various banks and from interest on saving bank account. Against these total receipts, the Society incurred an expenditure of Rs. 2.09 crores, thereby earned a surplus of Rs. 2.24 crore during the financial year 2016-17.

2. Electronics/IT/ITES Industry and Software Export from Haryana.

- (a) Having emerged as a preferred investment destination for the domestic as well as International investors, Haryana today is home to a number of multinational companies and corporate houses. IT & ESDM Policy and Entrepreneur and Start - up Policy, Communication & Connectivity Infrastructure Policy and Cyber Security Policy which were initiated during the year 2015-16 for providing several incentives for IT and ITes/BPO/ Electronic Manufacturing Factory and for facilitating investment by creating investor friendly environment, providing speedy clearances and developing reliable infrastructure. Most of the work on these policies has completed during the year 2016-17.
- (b) Besides above, e-mail Policy and Policy on use of IT Resources of the Government have been issued by the Department during the year. Under Haryana e-Seva Scheme, due to overwhelming response, 75 more services of the various Departments/ organisations were added during the year making the total services as 298.
- (c) Out of total 28 numbers of approved SEZs in IT/ITes Sector, six SEZs are functioning and remaining is in the process of development.
- (d) Upto during this year, 49 licenses granted to private entrepreneurs for establishment of IT/ITes Parks over an area of about 603.99 acres of land and project investment of more than Rs.12000 crores. Further, HSIIDC has made sufficient progress in development of infrastructure for Technology Park/ Electronics Hardware Technology Park to promote IT Sector at four locations *i.e.* Panchkula, IMT Manesar, Kundli and Rai in Sonapat in Haryana with total investment of Rs.5696 crores.
- (e) To aid the growth of the Electronics Systems Design and Manufacturing (EDSM) Sector, the area of District Gurgaon, Tehsil Bawala, Dharuhera Sub Tehsil, District Panchkula (Including Barwala Block and other Ind. Area), District Faridabad, District Palwal, Ambala District, Yamuna Nagar District, Jhajjar District and Sonapat District (All industrial areas including Kundli and Rai area approved by the State Government or its local authority) have been notified by Government of India.

- (f) Looking at the present scenario of growth of IT and IT Enabled Services Industries in the State, after Gurugram the department has initiated the steps for setting up of new STPI Centre at Panchkula for which land has been purchased from HSIIDC.
- (g) During the year 2016-17, Electronics & IT Export are estimated to be about USD\$ 116.01 Billion from India and Haryana's share is estimated to be 6.2% which works out to be USD\$ 7.2 Billion. The State currently accounts for 6.8% of the employment in the IT Sector throughout the country. More than 2.00 lac persons are working in IT/ITEs Sector.

3. ICT Infrastructure

- (a) **SWAN:** Under SWAN Scheme, all District Headquarters, Blocks/Sub-Divisions/Tehsils/Sub Tehsils, Haryana Civil Secretariat and Haryana Bhawan, New Delhi have been connected vertically and 1277 offices of various departments have been connected horizontally. State Data Centre has also been set up and 75 applications of various departments/ organizations and e-District projects have been hosted on Data Centre.
- (b) **NOFN:** Under National Optical Fibre Network, work of laying optical Fiber Cable completed during the year in 4051 Gram Panchayats. Wi-Fi hotspot system were installed in the villages of Faridabad, Sonapat, Rewari and Mahendergarh.
- (c) **ASKs:** Under 4000 Atal Seva Kendras established, services of 170 Departments were made in electronic mode and 37,94,725 transactions were conducted in 125 e-Disha Centre.
- (d) **Aadhaar Enrolment:** Under Aadhaar Enrolment, the State has achieved 103% Aadhaar saturation on the basis of population of 2015.

4. e-Services

- (a) **296 eServices** were provided online for benefit of citizens i.e. 170 Government to Citizen (G2C) eServices through Atal Seva Kendras and eDisha Centres, 15 G2C services on State Portal, 12 G2C Services of Govt. of India, 99 Business to Citizen (B2C) services.
- (b) Integration of RAS (Rapid Assessment System). 67 Departmental applications (Revenue, Agriculture, Home, HSIIDC, Social Justice, Sports, Science & Technology, PHE and Fisheries), were integrated over RAS. Besides this, 50 G2C services were planned to make available to the citizens through UMANG.

5. e-Governance Applications:

With a view to improving efficiency, reducing delays, increasing transparency and ease of business, various departments have rolled out e-Governance applications viz.

- (i) **CM Window:** A total number of 2,55,595 grievances were received out of which 2,28,617 have been disposed-off.
- (ii) **Revenue department:** Application for e-registration of appointments for property registration implemented to increase transparency in land registration system and also to provide ease of business, e-Stamping introduced.
- (iii) **CM e-Dashboard:** for improving efficiency of departments by monitoring Key Performance Indicators of departments
- (iv) **e-PMS (Project Management System):** to monitor important projects (of value greater than Rs. 10 crores) of Central & State Government
- (v) **Food& Supplies:** has introduced End-to-end computerization of TPDS covers data digitization, Ration Cards Management System, Online Allocation and Supply Chain Management, FPS automation. A database of beneficiaries identified under NFSA-2013 set up which complies with national data standards.
- (vi) **eBiz portal :** An online portal to enable clearance of industrial projects and redressal of grievances of investors at a single platform in a time-bound manner. Over 35 services were made available.
- (vii) **HSIIDC e-Seva portal:** An online portal created for citizen services such as allotment of plots/sites, automation of post allotment processes of estate management procedures and water & sewerage billing.
- (viii) **Birth & Death Registration:** Online Births & Deaths registration integrating *Aadhaar enrollment with birth registration implemented.*
- (ix) **Teachers Transfer Policy:** The School Education Department also notified Teachers Transfer Policy-2016 and integrated it with the Management Information system.

- (x) **Resident Database (SRDB):** About 1.68 Cr. Citizen Records contain the Aadhaar repository. 29 e-Services of various Departments have been integrated with SRDB to exchange data.
- (xi) **e-Office project: It was planned to introduce** e-office in IT Department, (ii) NIC, (iii) Hartron, (iv) IIT, (v) Public Health Department and Engineering Department on pilot basis.

6. Making financial transactions electronic & cashless.

- (a) State has made all payments through electronic mode. During the year, 91.12% payment amounting to Rs.54415.91 Cr was made electronically by State treasuries and around 4.45% amounting to Rs 1890.30 Cr payment was made to pensioners by A.G. and bank electronically.
- (b) State has provided the facility to pay online State Taxes through internet Banking and Credit Debit Card using payment aggregators. During the year 55% transactions were made online. Further, Payments have been made through NEFT/RTGS and PoS machines.
- (c) **Direct Benefit Transfer:** During the year State could save Rs.250 crore due to de-duplication in old age pensions, food subsidies and scholarship.
- (d) **Finance department** has implemented IFMS (Integrated Financial Management System) for better financial management of income and expenditure and HRMS (Human Resource Management System) for tracking employees service matters across their entire career.
- (e) **Commercial Taxes:** Department has rolled out Value Added Tax Management, Assessment, Collection System which provides On-line e-services like C-Forms, e-Application, e-Return etc. and enables excise department to be GST ready.

7. Skill Development Programme:

- (a) **National Digital Literacy Mission:** Under this programme, 2,26,928 candidates have trained in Appreciation of Digital Literacy (Level-1) course by the ASKs and 1,31,047 candidates have been successfully passed the examination and got their digital literacy certificate from Government of India.
- (b) Hartron is **imparting** Training to youth in IT skills through its 80 e-education Centres throughout the State. 30000 youths have been trained. Hartron under it Multi Skill development programme 1204 VLEs have been trained.
- (c) Haryana Knowledge Corporation Limited (HKCL) has established 245 franchise centers and 20924 candidates have been trained during the year.
- (d) Besides above, Government has also imparted Computer Training to more than 36000 Government employees till date.

8. Head of Department.

During the year under report the following held the charge of the post of Administrative Secretary and Secretary:-

- | | | |
|-------|------------------------------|-------------------------------|
| (a) | Administrative Secretary | |
| (i) | Smt. Keshni Anand Arora, IAS | 1.4.2016 to 1.5.2016 |
| (ii) | Sh.Devender Singh, IAS | 2.5.2016 to 31.3.2017 |
| (b) | Secretary/Special Secretary | |
| (i) | Sh.Vijayendra Kumar, IAS | 1.4.2016 to 25.04.2016 |
| (ii) | Sh. A.Sreenivas, IAS | 26.04.2016 to 13.02.2017(F/N) |
| (iii) | Sh.Vijayendra Kumar, IAS | 13.2.2017(A/N) to 31.03.2017 |

Chandigarh:
The 6th February, 2018

DEVENDER SINGH,
Principal Secretary to Government Haryana,
Electronics & Information Technology Department.